



Neutral Citation-2026: AHC:21501

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3354 वर्ष 2026

संजय सिंहयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 24 अन्य.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अखंड प्रताप सिंह, शोभित यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं, और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालाँकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील झांसी, जिला झांसी को निर्देश दिया जाए कि वे केस संख्या 59/2025 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या T202506370106774) (संजय सिंह बनाम माधुरी) का शीघ्रता से निपटारा करें।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर, उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) का उल्लेख करना उचित और उपयुक्त होगा, जो यह अनिवार्य करती है कि ऐसा आवेदन दायर किए जाने पर, संबंधित प्राधिकारी को कानून के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए, एक समय-सीमा के भीतर उसका निपटारा करना आवश्यक होगा। उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) में इस प्रकार लिखा है:-

"(3). इस धारा के तहत हर कार्यवाही, जहाँ तक संभव हो, उप-विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरी की जाएगी।"

5. उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील झांसी, जिला झांसी को यह निर्देश जारी किया जा रहा है कि वे उक्त मामले को हाथ में लें और उसका निपटारा, कानून के अनुसार सख्ती से और पूरी तेजी से—और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर—मामले के अपने गुण-दोष के आधार पर करें; बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो, तब तक कोई अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विरोधी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पांडेया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"